

सुप्रीम कोर्ट 4:1 बहुमत से फैसला सुनाया कि अदालतें मध्यस्थता और सुलह पर 1996 के कानून के तहत मध्यस्थता फैसलों को संशोधित कर सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सज्जद खान को और से बहुमत से लिए गए फैसलों में कहा गया है कि ऐसे फैसलों को संशोधित करने की शक्ति का प्रयोग अदालतों

जाना चाहिए। पीठ में मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सज्जद खान और न्यायमूर्ति बीरग आर्य न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति निरविवरन जॉर्ज मंजूर शानिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को मामले में अपना फैसला सुर्नाई रख लिया था।

CMYK

शासन को पत्र प्रेषित कर स्पष्ट रूप से कहा कि अगर एकमेकी महा विद्यालय देरानु देरानु में टीचिंग व नोन टीचिंग स्टाफ को रिक्त बल रह ४० फीसदी पदों को शीघ्र भर्ने की कवायद शुरू नहीं की जाति तो वह न्यायालय की पारण में जाने को बाध्य होंगे। अपने पत्र में रवीन्द्र जुगार ने यह भी अवगत कराया कि अगर हालात ऐसे ही रहें तो आने वाले तीन वर्ष बाद एकमेकी शारी महाविद्यालय में ताले लगने वाले हें, क्योंकि अगले तीन वर्ष बाद टीचिंग नोन टीचिंग वाले ९५ फीसदी सेवा निवृत्त हो जाएंगे।

[illegible]

पाक के लिए अगले 36 घंटे भारी

सूचना मंत्री ने आधी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा- हमारे पास है खुफिया जानकारी

इस्लामाबाद। पाक ने दावा किया है कि भारत उसके खिलाफ अगले 24-36 घंटों में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तारार ने बुधवार देर रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया। तारार ने कहा कि उन्हें विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली है कि भारत पहलगाम घटना के बहाने ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार रहा है और इस संकट के दर्द को सही मायने में समझता है। हमने दुनिया में हमेशा इसकी निंदा की है। तारार ने कहा कि अगर भारत कोई सैन्य हमला करता है, तो पाकिस्तान उसका निश्चिंत और कड़ा जवाब देगा। उन्होंने कहा कि हम हर कोमत पर पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे। तारार ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक भरोसेमंद, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच की खुले

तौर पर पेशकश की है, लेकिन भारत जांच से बचना चाहता है और टकराव का रास्ता अपनाना चाहता है। इसके पूरे क्षेत्र में विनाशकारी परिणाम होंगे। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इससे सतर्क रहना चाहिए। आगे होने वाले किसी भी खतरे और परिणाम की जिम्मेदारी पूरी तरह से भारत की होगी। इससे पहले पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी सोमवार को एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत जल्द ही हमला करने वाला है। आसिफ ने कहा कि आने वाले दिन बेहद अहम होंगे। चीन और सऊदी अरब समेत कई खाड़ी मुल्क दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष को रोकने की कोशिश में लगे हैं। अगर कुछ होगा तो 2-3 दिन में ही होगा। हालांकि अगले ही दिन आसिफ ने अपने बयान से पीछे हटते हुए कहा था कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है।



हमें विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली है कि पाक पहलगाम घटना के बहाने ऐसा कर सकता है, पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार रहा है। अगर भारत कोई सैन्य हमला करता है, तो पाकिस्तान उसका निश्चित और कड़ा जवाब देगा

...अताउल्लाह तारार, सूचना एवं प्रसारण मंत्री पाकिस्तान

हार्वर्ड में पाक कॉन्फ्रेंस पर गहराया विवाद

वॉशिंगटन। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट में हाल ही में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें पाकिस्तान वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब और अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शोख ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम 27 अप्रैल को हुआ था, जिसका आयोजन पाकिस्तानी छात्रों ने किया था। इस इवेंट के 4 दिन पहले यानी 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस को लेकर भारतीय स्टूडेंट्स ने हार्वर्ड के सामने अपना विरोध और आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद हार्वर्ड ने खुद को इस मुद्दे से अलग कर लिया और अपनी वेबसाइट से कार्यक्रम को जानकारी हटा दी। दो भारतीय स्टूडेंट सुरभि तोमर और रश्मि कोपरकर ने हार्वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को लेटर लिखा।

पहलगाम आतंकी हमले से उत्पन्न स्थिति पर नजर रख रहा अमेरिका



वॉशिंगटन। अमेरिका ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि वह पूरी स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर में और अधिक तनाव रोकने के लिए पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के संपर्क में हैं और उनसे संघर्ष से बचने का आग्रह कर रहे हैं। अमेरिका घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है और जिम्मेदार कृतीति को प्रोत्साहित करता है। सु ब्रूस ने दुनिया की नजरों के सामने शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए सहयोग की जरूरत पर जोर देते हुए पाकिस्तान के हालिया बयानों पर भी बात की।

CMYK

केन्या प्रतिनिधिमंडल का राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय का दौरा

नई दिल्ली। केन्या के नेशनल डिफेंस कॉलेज के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को यहां राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय का दौरा किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार केन्या के नेशनल डिफेंस कॉलेज के 20 सदस्य प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीनियर डायरेक्टिंग स्टफ (सेना) ब्रिगेडियर रिचर्ड वम्बुआ म्वांजिया ने किया। प्रतिनिधिमंडल का यह दौरा सेनाओं के बीच परस्पर सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत भी की और अनुभवों को

पाक ने यूएनएससी के बयान से टीआरएफ का नाम हटाया

विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में माना, इस आतंकी संगठन ने ली थी पहलगाम हमले की जिम्मेदारी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) का नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बयान से हटाने के लिए दबाव बनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बुधवार को सीनेट में दिए गए एक बयान में यह कबूल किया है। पाकिस्तान इस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद के निंदा बयान के लिए सभी सदस्यों की

सहमति जरूरी है। इशाक डार ने बताया कि अमेरिका ने हमले की निंदा करने के लिए एक प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि जब मुझे प्रस्ताव की कॉपी मिली तो उस पर केवल पहलगाम लिखा था और हमले के लिए द रेजिस्टेंस फोरम का नाम लिखा गया था। डार ने आगे कहा कि हमने इस पर विरोध जताया और कहा कि पाकिस्तान तब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक पहलगाम के साथ जम्मू और कश्मीर का भी जिक्र नहीं किया जाता और टीआरएफ का

नाम हटाया नहीं जाता। डार ने कहा कि उन्होंने 2 दिन तक इस प्रस्ताव पर साइन नहीं किया। इस दौरान कई देशों से उन्हें फोन आते रहे। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 25 अप्रैल को पहलगाम हमले को लेकर निंदा प्रस्ताव जारी किया था। इशाक डार ने कहा कि उन्होंने दुनियाभर के नेता यह कहते रहे कि निंदा प्रस्ताव न आने से पाकिस्तान के ऊपर आरोप आएगा। इसके बावजूद वे अपने दावे पर अड़े रहे। आखिरकार पाकिस्तान के दबाव में प्रस्ताव में बदलाव किया गया और

फिर यूएनएससी ने 25 अप्रैल को बयान जारी किया। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 25 अप्रैल, 2025 को पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की थी। इसमें 26 लोग मारे गए थे। इसमें भारत और नेपाल के लिए संवेदना जताई गई थी। यूएनएससी ने कहा कि आतंकवाद हर रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है और हमले के दोषियों व उनके समर्थकों को सजा मिलनी चाहिए। हालांकि इस बयान में द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने हमले की



जिम्मेदारी ली थी उसका जिक्र नहीं किया गया था। पहलगाम हमले का मकसद गैर-मुस्लिमों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक तनाव भड़काना था, लेकिन बयान में इसका भी जिक्र नहीं था।

चीन में जंगल की आग को लेकर ऑरेंज अलर्ट

बीजिंग। चीनी अधिकारियों ने बुधवार को 1 से 5 मई तक चीन के कुछ हिस्सों में जंगल की आग के लिए दूसरा सबसे उच्च-स्तर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राष्ट्रीय वन और चरागाह अग्नि-निर्बंधन कमान कार्यालय एवं आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने पांच दिवसीय हट्टी के दौरान हेबेई, शांक्सी, हेनान और शांक्सी के कुछ हिस्सों में जंगल की आग के लिए अलर्ट जारी किया। आपातकालीन प्रबंधन विभागों को आग के खतरे में बदलावों की बारीकी से निगरानी करने, प्रारंभिक चेतावनी और प्रतिक्रिया उपायों को लागू करने, आग के स्रोत

निर्बंधन को लगातार सुदृढ़ करने, आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने और जंगल की आग के जोखिम से प्रभावी ढंग से निपटने का निर्देश दिया गया है। जंगल और चरागाह की आग आठ प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। गौरतलब है कि एमईएम के एक अधिकारी यांग जुओंग ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर कहा, आम तौर पर, हाल के वर्षों में चीन की जंगल की आग में कुल मिलाकर गिरावट देखी गई है। आंकड़े बताते हैं कि, 1950 से 1989 तक, चीन में सालाना औसतन लगभग 16,000 जंगल की आग की घटनाएं हुईं।

वही, 1990 से 2020 के बीच यह संख्या घटकर लगभग 6,000 रह गई और 2021 से यह और भी कम होकर प्रति वर्ष 1,000 से भी कम रह गई है। यांग के अनुसार, जंगल और घास के मैदानों में आग लगने के कारणों को प्राकृतिक और मानवीय कारकों में वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें से 90 प्रतिशत से अधिक आग लगने की घटनाओं के लिए मानवीय कारक जिम्मेदार होते हैं। चीन में जंगल की आग के लिए चार-स्तरीय चेतावनी प्रणाली है, जिसमें लाल सबसे उच्च है, उसके बाद नारंगी, पीला और नीला है।



नाइजीरिया: आतंकवादी हमले में 14 लोगों की मौत

अबुजा। नाइजीरिया के बोर्नो प्रांत में संदिग्ध आतंकवादियों के हमले में एक समुदाय के कम से कम 14 लोग मारे गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बोर्नो के चिबोक स्थानीय सरकारी क्षेत्र के प्रमुख मोडू मुस्तफा ने संवाददाताओं को बताया कि आतंकवादियों के प्रतिबंधित बो. को हिराम समूह के सदस्य होने का संदेह है। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने सोमवार शाम दिवंगत नेता के लिए तीसरे दिन की प्रार्थना के दौरान चिबोक समुदाय पर हमला किया, अंधाधुंध गोलीबारी की और सात शोक संतप्त लोगों को मार डाला। स्थानीय स्वयंसेवकों ने हता.

हता की तलाश में आसपास के इलाकों की तलाशी ली, जिसके बाद मंगलवार को सात और शव बरामद किए गए। मुस्तफा के अनुसार, हिंसा के दौरान कई अन्य लोग गोली लगने के कारण अलग-अलग स्तर पर घायल हुए हैं। हमले के दौरान कई घरों में आग लगा दी गई। स्थानीय सरकारी अधिकारी ने कहा कि हता. हता की संख्या बढ़ सकती है। गौरतलब है कि बोको हिराम अपने सहयोगी समूह इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रांत के साथ मिलकर पूर्वोत्तर नाइजीरिया में इस्लामी राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। आतंकी समूहों ने लेक चाड बेसिन के दूसरे देशों में भी अपने हमले बढ़ा दिए हैं।

यूएस के साथ रिश्ते खत्म, विश्वासघात से चोट पहुंची: कार्नी

ओटावा। कनाडा। लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बन रहेंगे। आम चुनाव में उनकी पार्टी ने 343 में से 169 सीटें जीती हैं। ये 172 सीटों के बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 3 सीटें कम है। उनकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 144 सीटें जीत सकी। पार्टी का नेतृत्व कर रहे पियरे पॉलिवर अपनी सीट भी नहीं बचा सके। वे लिबरल पार्टी के उम्मीदवार से हार गए। लिबरल पार्टी की जीत के बाद उसे चौथी बार सत्ता में बने रहने का मौका मिला है। ए पार्टी के लिए बहुत बड़ा जनादेश है, क्योंकि दो महीने पहले तक पार्टी के जीतने की उम्मीद बहुत कम थी। पॉपुलैरिटी रेटिंग में पार्टी को सिर्फ 25 प्रतिशत पॉइंट मिले थे। जीत के बाद कार्नी ने पहले संबोधन में अमेरिका के साथ कनाडा के रिश्तों के अंत का ऐलान

किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने विश्वासघात किया है और यह बात कनाडा कभी नहीं भूलेगा। अमेरिका के साथ हमारा पुराना संबंध, जो लगातार बढ़ती एकजुटता पर टिका हुआ था, अब खत्म हो चुका है। अमे. रिका को ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी, जिस पर कनाडा ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से भरोसा किया और जिसकी वजह से कई साल तक हमारे देश में समृद्धि रही, अब खत्म हो चुकी है और यह हमारी भी नई सच्चाई है। हम अमेरिका के विश्वासघात के झटके से उबर चुके हैं, लेकिन हमें इस सबक को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब हमें खुद का ध्यान रखना होगा और सबसे जरूरी, हमें एक-दूसरे का ख्याल रखना होगा। जब मैं राष्ट्रपति ट्रम्प से मिलूंगा, तो यह दो स्वतंत्र देशों के आगे के संबंधों

पर चर्चा करने के लिए होगा। हम एक नया रास्ता तय करेंगे, क्योंकि यह कनाडा है और यहां जो होगा, वह हम तय करेंगे। हमें बड़े सपने देखने होंगे

और उससे भी बड़े काम करने होंगे। हमें वो काम करने होंगे जो पहले असंभव माने जाते थे, और ऐसी गति से करने होंगे, जो इसके पहले की

मार्क कार्नी और ट्रम्प ने मुलाकात पर सहमति जताई

ओटावा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने निकट भविष्य में व्यक्तिगत रूप से एक-दूसरे से मुलाकात करने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, कार्नी ने सोमवार को संसदीय चुनावों में जीत के एक दिन बाद मंगलवार को ट्रम्प से बात की, जिसमें अमेरिका की ओर से टैरिफ और विलय की धमकियाँ जैसे मुद्दे हावी रहे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने कनाडा और अमेरिका के स्वतंत्र, संप्रभु राष्ट्रों के रूप में एक साथ काम करने के महत्व को लेकर सहमति जताई। कार्नी ने अपने विजय भाषण के दौरान कई बार कनाडा-अमेरिका संबंधों का उल्लेख किया, कनाडावासियों को अमेरिका के साथ चल रही शत्रुता से उत्पन्न चुनौतियों की याद दिलाई।

